खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी फसलें उगाने को प्राथमिकता देते जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1991–92 के वर्ष की तुलना में 1992–93 के दौरान कुल कितनी भूमि के उपयोग में यह परिवर्तन हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में भूमि के उपयोग में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी परती भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेतम) (क) किसान, खाद्यान्न तथा नकदी फसलों सहित विभिन्न फसलों के लिए, उनकी संगत लाभप्रदता के आधार पर अपनी भूमि तथा अन्य संसाधनों का आवंटन करते हैं। इस बात के बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं हैं कि किसान देश के कुछ क्षेत्रों में सिंचित को छोड़कर भूमि संसाधनों के अपने आवंटन में खाद्यान्न की अपेक्षा नकदी फसलों के उत्पादन को स्थिर रूप से प्राथमिकता दे रहे हैं ।

(ख) राज्यों से 1992–93 की भू-उपयोग सांख्यिकी अभी देय नहीं हुई है। तथापि, मौजूदा सूचनाओं के अनुसार 1992–93 के दौरान खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्र के वर्ष 1991–92 की तुलना में अधिक होने की संभावना है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है । फिर भी कृषि और सहकारिता विभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मृदा अपरदन तथा भूमि निम्न कोटिकरण से प्रभावित 17 लाख हैक्टेयर भूमि के विकास, सुधार तथा पुनर्स्थापना के लक्ष्य का प्रस्ताव किया है ।

Cultivation of Cotton

1394. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to channelise and control cotton export through Agriculture Ministry;

(b) whether Government propose to encourage cultivation of cotton for export purposes;

(c) if so, what are the areas selected for intensifying cotton cultivation; and

(d) whether chemical inputs will be easily made availagle for this purpose on a pilot project basis?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a): There is no proposal to channelise and control cotton export through Agriculture Ministry.

(b) and (c): The Government is implementing Intensive Cotton Development Programme (ICDP) in all the important cotton growing States, namely, Andhra Pradesh; Gujarat, Haryana, Karnataka; Madhya Pradesh, Maharashtra Orissa Punjab Rajasthan, Tamil Nadu and Uttar Pradesh. The Programme aims at increasing production of all types of cotton to meet domestic requirement as well as to produce surplus for exports.

(d): Financial assistance is being provided to. the States under ICDP for supply of inputs including plant protection chemicals.